साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 04 अगस्त से 10 अगस्त 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 05 में...
अपने ही सवालों में घिरा विपक्ष

पेज 12 में...
धर्म, आस्था, और व्यवस्था हलाक...

वर्ष : 01 अंक : 22 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 08 कुम्हारी टोल प्लाजा पर 'अवैध वसूली'

काम तो करो पोस्टर बॉय...

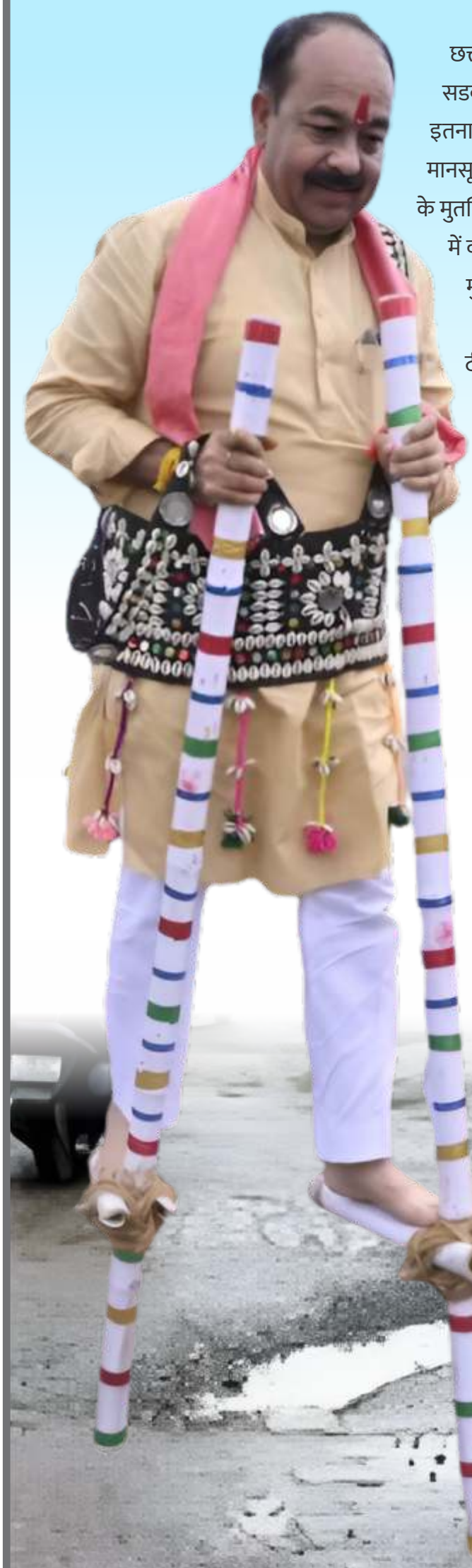

छत्तीसगढ़ राज्य की जनता अभी भी सुरक्षित और गुणवत्ता वाली सडकों के लिए तरस रही है। राज्य अपनी जवानी की रुमानियत में इतना खो गया है कि हमारे कर्ता पुरुष पोस्टर बॉय बनकर रह गए हैं। मानसून में खेती करते दिखेंगे, हरेली में गेड़ी चढ़ेंगे और ना जाने मौसम के मुतल्लिक स्वांग रचकर ख़बरों की सुर्खियां बनेंगे लेकिन सहीं मायनों में वो काम नहीं करेंगे। एक्सप्रेस-वे, सर्विस रोड, बायपास हो या फिर मुख्य राजमार्ग खस्ताहाली का शिकार हैं। यहां सिर्फ पोस्टर बॉय मंत्री ही गेड़ी में चल सकते हैं। खुशकिस्मती से राष्ट्रीय राजमार्ग ठीक-ठाक हैं तो वहां घुमंतू मवेशी और लोगों की जान खतरे में है। फर्क क्या पड़ता है...मंत्री जी पोस्टर बॉय बनकर सिर्फ फोटो सेशन में लगे हैं। काम करने के बजाए फोटो सेशन राजनितिक सफर छोटा कर देता है शायद इसका उन्हें भान नहीं।

भाठागांव से तेलीबांधा तक गडढों का 'हाईवे'

हर किलोमीटर पर 30 से ज़्यादा गड्ढे, बारिश ने बिगाड़ी हालत

रायपुर। राजधानी रायपुर के नेशनल हाईवे से सटे सर्विस रोड इन दिनों गड्ढों का पर्याय बन चुके हैं। भाठागांव से लेकर तेलीबांधा चौक तक लगभग चार किलोमीटर लंबे मार्ग का हाल यह है कि हर एक किलोमीटर में 30 से अधिक छोटे-बड़े गड्ढे देखने को मिले। हाल ही में हुई तेज बारिश ने डामर को उखाड़ डाला है और भारी वाहनों के दबाव ने स्थिति और खराब कर दी है।

पचपेड़ी नाका पर सबसे भयावह स्थिति

भाठागांव से तेलीबांधा तक कई जगह हालात खराब हैं, लेकिन पचपेड़ी नाका के पास सर्विस रोड की हालत सबसे दयनीय है। यहां बड़े-बड़े गड्ढों और उखड़े डामर की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। महासमुंद, धमतरी और दुर्ग से आने वाले भारी वाहन यहीं से गुजरते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

दोपहिया चालक सबसे ज्यादा परेशान

खराब सड़कों की वजह से बड़ी गाड़ियां सेकेंड गियर में रेंगने को मजबूर हैं। इनके पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को मजबूरी में बड़ी गाड़ियों को काटकर निकलना पड़ता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है।

साप्ताहिक शहरसत्ता

रोड कार्नर पर गहरी खाई जैसी स्थिति

भाठागांव से तेलीबांधा तक कई जगह सर्विस रोड और मेन रोड के बीच का गैप काफी गहरा है। ऐसे में बड़े वाहन तो क्या, छोटे चारपहिया और दोपहिया वाहन चालक भी सड़क से उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।

गांवों की सड़कें और भी बदहाल

जब राजधानी के सर्विस रोड की हालत इतनी खराब है, तो ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर बंजारी के आगे सड़कें बेहद जर्जर हैं, वहीं बलौदाबाजार मार्ग पर विधानसभा के आगे की सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं।

मरम्मत अब बारिश के बाद

पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ज्ञानेश्वर कश्यप ने बताया कि बारिश के चलते सड़क सुधार कार्य अभी संभव नहीं है। आठ से दस दिनों में सर्वे रिपोर्ट आने की उम्मीद है। सितंबर के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर मरम्मत का काम शुरू होगा।

सड़क निर्माण पर भूपेश और अरुण साव आमने-सामने

सिर्फ 2 सड़क मंजूरी के दावों पर उपमुख्यमंत्री साव बोले– 717 सड़कें स्वीकृत

छत्तीसगढ़ की सियासत में सड़क निर्माण बड़ा मुद्दा बन गया है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के बीच इस मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली।

भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर को आरटीआई से मिले दस्तावेज का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने केवल दो सड़कें ही स्वीकृत की हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि साव के गृह जिले मुंगेली में महज़ 0.5 किमी लंबी सड़क की स्वीकृति मिली है। बघेल ने यह बयान मीडिया और अपने अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया।

इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा— “यह भूपेश का झूठासन नहीं, बल्कि विष्णुदेव का सुशासन है।”

साव ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 20 महीनों में 4492 करोड़ रुपये की लागत से 717 सड़कें, पुल और भवन स्वीकृत हुए हैं। सिर्फ मुंगेली जिले में ही 82 कार्यों के लिए 363 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। भूपेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा- “जो 5 साल में 5 किमी सड़क नहीं बना पाए, वे अब झूठ की सड़क बनाकर राजनीति कर रहे हैं।”सड़क निर्माण का यह विवाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव का नया केंद्र बन चुका है।

नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का निरीक्षण करते उपमुख्यमंत्री अरुण साव

एक साल में सड़क निर्माण ठप, सरकारी दावों की खुली पोल

शहरसत्ता | रायपुर

छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूचना अधिकार (आरटीआई) से मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा सरकार ने पिछले एक साल में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई। दस्तावेज़ों में साफ़ दर्ज है कि बिलासपुर परिक्षेत्र के मुंगेली जिला अस्पताल तक केवल 0.50 किलोमीटर सड़क और सरगुजा परिक्षेत्र के मैनपाट के कोटछाल से गौतम चौक तक महज़ 0.45 किलोमीटर सीसी रोड बनाने की स्वीकृति दी गई है।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने गुरुवार को दस्तावेज़ सार्वजनिक करते हुए कहा — “यह साबित करता है कि सड़क की समस्या सरकार की ही बनाई हुई है। जनता हताश और परेशान है, और भाजपा नेताओं के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क निर्माण विभाग ने कोई ठोस पहल नहीं की। सरकार में बैठे लोग जनता की मूलभूत समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। यह सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर सड़क बना रही है, ज़मीन पर नहीं। जनता अब सवाल कर रही है कि जब सड़क जैसी बुनियादी ज़रूरत पर ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो प्रदेश का विकास किस दिशा में जाएगा।

डेढ़ साल में 4492 करोड़ की 617 सड़कें और 91 पुलों को मंजूरी

शहरसत्ता ब्यूरो | रायपुर।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड स्वीकृतियां दी हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, करीब डेढ़ साल में 4492 करोड़ रुपए की लागत से 617 सड़कों और 91 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 551 करोड़ रुपए की लागत से 72 सड़कें, 6 पुल और 2 लोक निर्माण भवन को हरी झंडी मिली।

वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ रुपए की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन स्वीकृत हुए। वहीं, वर्ष 2025-26 में 31 जुलाई तक 1350 करोड़ रुपए की 145 सड़कें, 48 पुल और 6 भवन के कार्यों की मंजूरी प्रदान की गई।

इस तरह दिसंबर 2023 से अब तक कुल 4492 करोड़ रुपए के 617 सड़क, 91 पुल और 7 भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई नए प्रोजेक्ट्स मंजूरी की प्रक्रिया में हैं। केवल मुंगेली जिले में ही दिसंबर 2023 से अब तक 363 करोड़ रुपए की लागत के 82 कार्यों की मंजूरी मिली है। इनमें वर्ष 2023-24 में 59 करोड़ के 11 कार्य, 2024-25 में 242 करोड़ के 55 कार्य और 2025-26 में अब तक 61 करोड़ के 16 कार्य शामिल हैं।

फादर टी. लोर थे छत्तीसगढ़ के पहले मिशनरी

4 से 6 लाख ईसाई आबादी तक का सफर और अब सख्त कानून की तैयारी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हाल के वर्षों में सामाजिक और राजनीतिक टकराव बढ़ते जा रहे हैं। 25 जुलाई 2025 को दो ननों की गिरफ्तारी और 28 जुलाई को कांकेर में ईसाई व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर हुई हिंसा के बाद यह बहस फिर तेज हो गई है—कि राज्य में ईसाई धर्म की जड़ें कहां से और कैसे मजबूत हुईं? और अब सरकार इस पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठा रही है?

157 साल पुरानी जड़ें: विश्रामपुर से शुरू हुआ ईसाई मिशन

छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म की शुरुआत 1868 में बलौदाबाजार के छोटे से गांव विश्रामपुर से हुई थी। जर्मनी में जन्मे रेवरेंड फादर ऑस्कर थियोडोर लोर ने यहां प्रदेश की पहली मिशनरी स्थापित की थी। उन्होंने गांव में स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल जैसे संस्थान बनाए और लोगों को शिक्षा-चिकित्सा देकर अपने धर्म से जोड़ा। 1870 में विश्रामपुर में केवल 4 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन 1883 तक ये संख्या 258 हो गई। 1884 तक रायपुर, बैतलपुर, परसाभदर जैसे अन्य केंद्रों में 1,125 लोग ईसाई बन चुके थे। आज छत्तीसगढ़ में ईसाई आबादी 6 लाख से अधिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, राज्य की कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ थी, जिसमें 1.92% यानी 4.90 लाख लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे। अब अनुमान है कि यह संख्या बढ़कर 6 लाख के पार हो चुकी है।

पहला चर्च और कब्रिस्तान: विश्रामपुर में बने इम्मानुएल चर्च की खासियत

15 फरवरी 1873 को बलौदाबाजार के विश्रामपुर में छत्तीसगढ़ का पहला चर्च, इम्मानुएल चर्च, बनना शुरू हुआ और 29 मार्च 1874 को तैयार हुआ। चर्च से लगा कब्रिस्तान, जिसमें खुद फादर लोर की भी कब्र है, आज भी वहीं स्थित है। मिशनरी के कार्यों में उनके दोनों बेटे कार्ल और जूलियस भी शामिल थे। चर्चाओं के अनुसार, कार्ल की बाघ के हमले में मौत हो गई थी, और जूलियस की डिप्रेशन से मृत्यु हुई।

कैसे फैला ईसाई धर्म

पत्रकार आलोक पुतुल बताते हैं कि ईसाई मिशनरी ने उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाई, जहां सरकार की बुनियादी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नहीं पहुंचे। लोगों की जरूरतों को धर्म से जोड़ा गया, जिससे धर्मांतरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ी। बाइबिल के अंशों को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर स्थानीय भाषा में धर्म प्रचार किया गया। यह मिशन गांव-गांव तक फैलता गया।

वर्तमान टकराव : गिरफ्तारी हिंसा और आत्महत्याएं

1. ननों की गिरफ्तारी और राजनीति

25 जुलाई 2025 को दो ईसाई मिशनरी ननों को कथित रूप से धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुर्ग जेल पहुंचा और आरोप लगाया कि सरकार उन्हें झूठे केस में फंसा रही है।

2. कांकेर में कब्र से शव निकाला गया

28 जुलाई को कांकेर में एक ईसाई व्यक्ति की दफन प्रक्रिया को लेकर 500 से ज्यादा लोगों ने चर्च और घरों पर हमला किया। कब्र से शव बाहर निकालना पड़ा। मृतक के भाई ने हत्या कर शव गाड़ने का आरोप लगाया।

3. आत्महत्या के दो मामले, धर्मांतरण का दबाव कारण बना

7 दिसंबर 2024, धमतरी: लीनेश साहू (30) ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वॉट्सऐप स्टेटस में लिखा—"पत्नी, सास-ससुर और साली ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।"

20 दिसंबर 2024, बालोद: सूरज देवांगन (35) ने आत्महत्या की। मरने से पहले शिकायत दी थी कि पत्नी और ससुराल पक्ष उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रहे हैं।

धर्मांतरण पर गरमाई सूबाई सियासत

कानून, आंकड़े और पक्ष-विपक्ष की टकराहट ने बढ़ाया विवाद

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बार फिर राजनीति, कानून और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। दुर्ग में दो ननों की गिरफ्तारी के बाद इस मुद्दे ने नई आग पकड़ ली है। राज्य की बीजेपी सरकार अब धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। वहीं ईसाई और आदिवासी समाज के संगठन, दोनों की प्रतिक्रियाएं भी इस बहस को और व्यापक बना रही हैं।

धर्मांतरण कानून: वर्तमान और प्रस्तावित बदलाव

मौजूदा कानून- छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968,

सरकार का मत-यह कानून अब "अपर्याप्त" है, पुलिस के पास स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं।

नया कानून प्रस्तावित- सख्त और व्यावहारिक प्रावधान, स्पष्ट दंडात्मक संरचना के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि नया कानून आगामी सत्र में पेश किया जाएगा और सभी संगठनों से कानूनी दायरे में काम करने की अपील की है।

एनजीओ और विदेशी फंडिंग: धर्मांतरण से जुड़ी चिंताएं

- 364 एनजीओ को 2020 तक विदेशी फंडिंग प्राप्त होती थी
- इनमें से 84 पर प्रतिबंध और 127 स्वतः बंद
- वर्तमान में 153 सक्रिय एनजीओ, जिनमें बड़ी संख्या बस्तर-जशपुर क्षेत्रों में कार्यरत हैं
- ईसाई मिशनरी नेटवर्क से जुड़ाव होने का संदेह, जिसकी जांच की मांग तेज़

धर्मांतरण के दर्ज मामले: (2020–मार्च 2025)

वर्ष	दर्ज मामले
2020	1
2021	7
2022	3
2023	0
2024	12
2025 (मार्च तक)	4
कुल	**23 मामले**

इनमें से अधिकतर मामले बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों से जुड़े हैं।

ईसाई समाज की प्रतिक्रिया: 'गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा'

ईसाई फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने धर्मांतरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा: "अगर हम धर्मांतरण करते तो आज पूरा देश ईसाई होता। भारत में धर्मांतरण कलेक्टर की अनुमति से ही वैध है, बाक़ी सब झूठ और अफवाह है।" उनका आरोप है कि बजरंग दल जैसे संगठन धर्मांतरण के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं।

ईसाई आबादी के आंकड़े (अरुण पन्नालाल के अनुसार):

वर्ग	अनुमानित संख्या
कुल ईसाई आबादी (छत्तीसगढ़ में)	18 लाख
रजिस्टर्ड धर्मांतरित	4 लाख
- रोमन कैथोलिक	2.25 लाख
- मेनलाइन प्रोटेस्टेंट	1.25 लाख
- CBN इत्यादि	30–40 हजार
अन्य (अनुयायी पर धर्मांतरण नहीं)	लगभग 12 लाख

आदिवासी समाज की चिंता: धर्मांतरण और घुसपैठ दोनों खतरा

छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के अध्यक्ष बी.एस. रावटे ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई और कहा: "धर्मांतरण आदिवासी अस्तित्व और संस्कृति पर हमला है। इस पर कड़ा और स्पष्ट कानून जरूरी है।"

मुद्दे की जड़: धर्मांतरण अब सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक और प्रशासनिक विषय

धर्मांतरण का मुद्दा अब सामाजिक-धार्मिक बहस से आगे बढ़कर राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक चुनौती बन गया है। आने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तावित नया विधेयक, राज्य की राजनीतिक दिशा और जनजातीय-संवैधानिक अधिकारों की संरचना पर गहरा असर डाल सकता है।

राजनीतिक घमासान: कांग्रेस ने साधा निशाना

"ननों की गिरफ्तारी कोर्ट को बताए बिना करना दर्शाता है कि यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। बीजेपी केरल में गिरफ्तारी का विरोध करती है, छत्तीसगढ़ में समर्थन देती है। ये दोहरा रवैया है।"

भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री)

"धर्मांतरण बीजेपी का चुनावी हथियार है। हर बार विधानसभा सत्र से पहले कानून लाने की बात होती है, लेकिन सिर्फ तारीखें बढ़ती हैं, कानून नहीं आता।"

दीपक बैज (कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष)

साप्ताहिक शहर सत्ता

रजत जयंती वर्ष में होगा नए विधानसभा भवन का लोकार्पण

आ सकते हैं पीएम मोदी...

रायपुर। राज्य बनने के 25 साल बाद, इस साल राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ विधानसभा नवा रायपुर के विधानसभा भवन में शिफ्ट हो जाएगी। 52 एकड़ में बन रहे इस परिसर का सिविल वर्क मोटे तौर पर पूरा हो गया और फिनिशिंग तेजी से चल रही है। विधानसभा के स्पीकर डा. रमन सिंह के साथ रविवार की शाम सीएम विष्णुदेव साय, पीडब्लूडी मंत्री अरुण साव, अजय जाम्वाल और पवन साय ने परिसर का निरीक्षण किया। सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और पीडब्लूडी सचिव डा. कमलप्रीत सिंह भी साथ थे। स्पीकर डा. रमन ने बताया कि विधानसभा सदन, विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष, मुख्यमंत्री का कक्ष तथा सम्पूर्ण परिसर का काम लगभग पूरा हो गया है। सितंबर में भवन तैयार हो जाएगा। इस विधानसभा भवन में 200 विधायकों के बैठने की क्षमता बनाई गई है। अभी 90 विधायक हैं, यानी 110 चेयर अभी खाली रहेंगी। जैसे-जैसे परिसीमन होगा, संख्या बढ़ती जाएगी। विधानसभा के निरीक्षण से बाद सीएम साय ने अफसरों को निर्देश दिए कि निर्माण सितम्बर तक की समय सीमा पर हर हाल में पूरा कर लिया जाए, ताकि राज्योत्सव (1 नवम्बर) के अवसर पर इसे जनता को समर्पित किया जा सके। बता दें कि सीएम हाल के दिल्ली दौरे में राज्योत्सव के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण देकर आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि रजय जयंती वर्ष पर पीएम राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं।

नए विधानसभा भवन के बारे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि यह केवल शासकीय संरचना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक भव्यता एवं वैभव का प्रतीक बनेगा। इस परिसर के निर्माण की कड़ी निगरानी कर रहे पीडब्लूडी सचिव डा. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इस भवन में तीन प्रमुख विंग निर्मित किए जा रहे हैं। विंग-ए में विधानसभा सचिवालय, विंग-बी में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय सहित विधानसभा सदन व सेंट्रल हॉल, तथा विंग-सी में उप मुख्यमंत्रियों एवं अन्य मंत्रियों के कार्यालय स्थित होंगे। सदन में 200 विधायकों के बैठने की क्षमता के साथ-साथ 500 दर्शकों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी होगा। परिसर में 700 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ के दो सरोवर भी डेवलप किए जाएंगे।

सावन में सीएम साय ने किया रूद्राभिषेक

रायपुर। सावन मास के पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र से प्रारंभ हुई भव्य कांवड़ यात्रा में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का रूद्राभिषेक किया और छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस धार्मिक आयोजन को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मारूति मंगलम भवन, गुढ़ियारी से हजारों की संख्या में कांवड़िए पदयात्रा पर रवाना हुए, जो महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जल अर्पित करते हैं। उन्होंने इस परंपरा को श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। सीएम ने कहा कि सावन में शिवभक्तों द्वारा निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राएं न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन हैं, बल्कि ये आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक समृद्धि को भी सशक्त करते हैं। महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ मंदिर की महत्ता का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे राजधानी का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बताया, जहां सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक हेतु एकत्र होते हैं।

बाल्को को लाभ पहुंचाने के लिए डीएमएफ फंड का दुरुपयोगः कंवर

कोरबा। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से किए जा रहे एक सड़क निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दर्री डेम से बाल्को परसाभाटा तक प्रस्तावित सड़क का निर्माण बाल्को कंपनी को फायदा पहुंचाने के इरादे से किया जा रहा है और इसके लिए डीएमएफ फंड का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने इस स्वीकृति को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए कहा है कि यह कार्य बाल्को कंपनी से राशि लेकर ही कराया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री कंवर ने यह पत्र प्रधानमंत्री के साथ-साथ केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग के संचालक को भी भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमएफ फंड का उपयोग जनकल्याण के बजाय एक निजी कंपनी को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जो पूरी तरह से नियमों और उद्देश्य के खिलाफ है।अपने पत्र में ननकीराम कंवर ने कांग्रेस शासनकाल का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उनके और पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल के कार्यकाल में एसईसीएल से स्वीकृति लेकर कई विकास कार्य कराए गए थे, जिनमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले भी खनन कंपनियों से ही राशि लेकर सड़कें बनती थीं, तो अब डीएमएफ फंड से इस परियोजना को क्यों स्वीकृत किया जा रहा है।

रायपुर-जबलपुर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन, 8 घंटे में तय करेगी 410 किमी

पर्यटन, व्यापार और शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रविवार को रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से 11701 रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर को उन्होंने "प्रदेश की रेल विकास यात्रा में ऐतिहासिक दिन" बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया।

नई एक्सप्रेस सेवा छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ते हुए क्षेत्रीय संपर्क को और अधिक मजबूत करेगी। 410 किलोमीटर की दूरी केवल 8 घंटे में पूरी होगी, जिससे यात्रियों का समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इस उद्घाटन समारोह के दौरान गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उसी समारोह में रीवा-पुणे एक्सप्रेस और भावनगर-अयोध्या एक्सप्रेस का भी शुभारंभ हुआ।

पगडंडियों पर जीवन, मगर इरादों में शहरी आत्म स्वावलंबन

अबूझमाड़ का कोड़तामरका, जहां विकास नहीं, आत्मनिर्भरता की रौशनी

नारायणपुर। घने जंगलों की गोद में बसा, पथरीले रास्तों और उफनती नदियों से घिरा एक गांव—कोड़तामरका। यह कोई आम गांव नहीं, बल्कि आजादी के 75 साल बाद भी जहां न सड़क है, न स्कूल, न डॉक्टर, न बिजली—फिर भी यहां खड़ी है एक संगठित, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर बस्ती, जिसने सरकारी नाकामी पर अपने जुगाड़ और सामाजिक सहयोग से करारा जवाब दिया है।

कोड़तामरका तक पहुंचने के लिए नारायणपुर जिले के कुतुल से करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जो सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि विकास से कटेपन की गवाही है। हमारी टीम ने तीन घंटे तक पैदल चलकर इस गांव की हकीकत देखी—जंगल की सिहरन, बरसाती नदियों की उफनती धाराएं और जानलेवा चढ़ाइयों ने रास्ते में बार-बार चेताया कि यह वो यह गांव छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम अबूझमाड़ अंचल में आता है, जो दशकों से नक्सल प्रभाव में रहा है। यहां कोई सड़क नहीं, कोई पक्का पुल नहीं। स्कूल नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं। पर ग्रामीणों की एकता और सहकारिता ने जो खड़ा किया है, वह किसी सरकारी विकास योजना से कम नहीं। सरकार की मुफ्त राशन योजना के तहत मिलने वाले 35 किलो चावल को लाने के लिए ग्रामीणों को कंधे पर बोरी उठाकर, दो पहाड़, कई नाले और जंगल पार कर धुरबेड़ा जाना पड़ता है। यह सिर्फ भूख मिटाने की कोशिश नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जिद है।

शिक्षा और स्वास्थ्य: सबसे बड़ी गैर-मौजूदगी

गांव में न तो कोई स्कूल है, न ही नियमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। एक टूटी झोपड़ी में "कागजों पर" आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, जहां 30 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल और भी बुरा। महीने में एक बार कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता आता है और दवाएं छोड़कर चला जाता है। गंभीर मरीजों को 'कांवड़' में लिटाकर मीलों दूर ले जाया जाता है।

नक्सल स्मारक: डर का मौन पहरेदार

गांव में तीन नक्सली स्मारक—साकेत, शोभाराय और ममता—स्थानीय जमीन पर डर और दबाव की पहचान बने हुए हैं। हालांकि पुलिस इन स्मारकों को तोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी नक्सल प्रभाव की मौजूदगी दर्शाता है।गांव के बीच बहने वाली नदी पर ग्रामीणों ने बांस और लकड़ी से स्थानीय जुगाड़ पुल बनाया है, जो बारिश में उनकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद सहारा बनता है। यह पुल उस देशी इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जिसे न किसी ठेकेदार ने बनाया और न ही किसी योजना में मंजूरी मिली—बल्कि केवल ज़रूरत और सामूहिक बुद्धिमत्ता से।

टूटी सोलर लाइटें और बंजर योजनाएं

तीन साल पहले गांव में कुछ सोलर लाइटें और एक वाटर टैंक लगाया गया था। आज लाइटें खराब हो चुकी हैं और वाटर टैंक की पाइपलाइन से आज तक एक भी बूंद पानी नहीं निकला है। गांव अब भी मिट्टी के तेल और टॉर्च पर आश्रित है।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

पूत-कपूत तो का धन संचय

छत्तीसगढ़ की नौकरशाही और सियासी लाल फीताशाही से सभी वाकिफ हैं। मलाईदार विभागों में सरकारी खरीदी हो या निर्माण कार्य सभी में भ्रष्टाचार जैसे शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग या फिर परिवहन के साथ आबकारी दशकों से ये सधारणे का नाम नहीं लेते। छत्तीसगढ़ में 25 गुना, 30 गुना अधिक दर पर सरकारी खरीदी का धारावाहिक मंत्री से लेकर विभाग प्रमुख तक देख चुके हैं। बस सुधरने को कोई तैयार नहीं। अगर खुशकिस्मती से सियासत का निजाम बदल जाये तो फिर पुराने के सिर में ठीकरा फोड़ना और आसान है। प्रदेश की सड़कों का हाल सब जानते हैं। राजधानी रायपुर से लेकर सभी बड़े संभागों और जिलों में रोड-रास्ते में कितना खर्च किसने किया और फिर भी उन सड़कों का एक बारिश में क्या हाल है किसी से छुपा नहीं। वैसे तो लोक निर्माण विभाग के अब तक के मंत्रियों में पोस्टर बॉय अरुण साव उपमुख्यमंत्री रहते हुए भी इस बारिश लोक निर्माण मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहे।

विपक्ष और अख़बार राजधानी रायपुर समेत सूबे के सबसे बदहाल राजमार्गों के हालात से उन्हें बाख़बर कर चुके हैं। लेकिन उनके महकमे के विवादित ईएनसी पर उन्हें ज्यादा एतबार है। ईएनसी और मंत्री फुनगी में दिया बरते दीखते हैं और जिन सड़कों का निर्माण ठेका में गड़बड़ी उजागर होती है तो बेलगाम ठेकेदार हिंसक हो कर मार्के गटर में फेंक देते हैं। रिकवरी तो दूर जिन अधिकारीयों के समय गड़बड़ियां हुईं उन्हें बक्श दिया गया है। भवन, सड़क, सर्विस रोड और एक्सप्रेस-वे निर्माण की गुणवत्ता पोस्टर बॉय मिनिस्टर और उनके अफसर अगर पूरी नहीं सिर्फ थोड़ी इमानदारी से देख ले तो गेड़ी चढ़ना मुश्किल हो जायेगा। छत्तीसगढ़ में सिस्टम इतना बेपटरी हो चुका है कि जिस काम में पैसा नहीं, उधर सरकारी मुलाजिमों को देखना गवारा नहीं। महकमे की रस्म थी पहले नजराना लेने की अब तो इंद्रावती से महानदी तक जबराना वसूली है।

विस्मित करने वाली बात है कि राज्यों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री से मिलना आसान नहीं होता। वो भी नरेंद्र मोदी जैसे पीएम से तो और भी मुश्किल है। आमतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साल में एक-दो दफे ही पीएम से मिलने का मौका मिल पाता है। मगर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शपथ लेने के बाद डेढ़ साल में पांच बार पीएम मोदी से वन-टू-वन मिल चुके हैं। हर दो-तीन महीने में उनकी पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात हो जाती है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग में खरीदी घोटाला, बड़े-बड़े ठेके और बदहाल सड़कों के अलावा पुरानी कारस्तानियों पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं होता ?

अपने ही सवालों में घिरा विपक्ष

नवनीत गुर्जर

लगभग तीन महीने से हवा में तैर रहे सवालों के जवाब मिल गए। पहलगाम के। ऑपरेशन सिंदूर के और इन दोनों से जुड़े अन्य मामलों के भी। हालांकि भारत को कितना और क्या नुकसान हुआ, जैसे कुछ सवाल अनुत्तरित ही रहे और दलगत राजनीति से ऊपर उठें और केवल देश के लिए सोचा जाए तो ऐसे सवाल अनुत्तरित ही रहने चाहिए। सरकारों के पास कुछ तो गोपनीय रहना ही चाहिए।

जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग, जो दल सरकार में रह चुके हैं, उन्हें व्यवस्थाओं के बारे में सब पता है। इसके बावजूद जो और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, वे कुछ हद तक बचकाने ही कहे जाएंगे। बहरहाल, विपक्ष के पास अब बिहार की मतदाता सूची के अलावा कोई प्रश्न नहीं बचा है। हालांकि पिछले ग्यारह सालों में विपक्ष के पास कई मुद्दे आए, कई ऐसे विवाद आए, जिन पर वह सरकार को घेर सकता था। बाकायदा सबूत देकर सरकार के खिलाफ डंका बजा सकता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष इतना मजबूत है या उसकी राजनीति इतनी पक्की है कि विपक्ष की इतने वर्षों में एक नहीं चली।

सही है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन उसमें उतनी ही मजबूत समझदारी, परिपक्वता भी होनी चाहिए ताकि वह देशहित के मामलों में सत्ता पक्ष या सरकार का सकारात्मक सहयोग कर सके और दिशा भटकने पर सरकार के खिलाफ खड़ा होकर सही दिशा भी बता सके। ग्यारह वर्षों में तमाम विपक्षी पार्टियों ने शायद ही ऐसा कुछ किया हो! चुनाव चाहे हरियाणा का हो, या महाराष्ट्र का, वोटिंग मशीनों के खिलाफ विपक्ष सिर्फ चिल्लाता रहा है। कोई सबूत आज तक पेश नहीं कर सका। न जनता के सामने। न सुप्रीम कोर्ट के सामने। कभी कहा हरियाणा में कुछ वोटिंग मशीनों में बैटरी का परसेंटेज कम, कुछ में नब्बे से भी ज्यादा कैसे?

तो कभी कहा महाराष्ट्र में एक प्रत्याशी को अपना ही वोट नहीं मिला, यह कैसे संभव है? लेकिन इन सब बातों का कोई पुख्ता सबूत विपक्ष कभी नहीं दे पाया। महाराष्ट्र के मामले में तो चुनाव आयोग सिद्ध भी कर चुका कि उस प्रत्याशी को वोट मिले थे और यह वोटिंग मशीन से भी साबित हो चुका। इस तरह के आरोपों पर जब सत्ता पक्ष सवाल करता है कि विपक्ष जीतता है तब वोटिंग मशीनें शुद्ध और अच्छी कैसे हो जाती हैं? तो विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में उसके अपने सवाल भी लोगों को हास्यास्पद लगने लगते हैं। जहां तक बिहार का मामला है, यहां मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि उसकी पद्धति शुद्ध और निष्पक्ष है। हो सकता है व्यवस्था की खामियां यहां भी हों! जिन लोगों को मतदाता के डिटेल्स कलेक्ट करने का जिम्मा सौंपा गया है वे इसमें तरह-तरह की कोताही बरत रहे हों। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि इस सूची में कोई भी खामी रहती है तो सभी दलों को यह सौंपी जाती है। यहां तक कि आम आदमी से भी आपत्ति मंगाई जाती है। कोई भी व्यक्ति पुख्ता सबूत देकर इस सूची में सही नाम जुड़वा सकता है और गलत नाम हटवा भी सकता है। फिर दिक्कत क्या है? कोई तो बताए? दरअसल एक पक्ष यानी जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं, उनका कहना है कि बहुत से नाम काटे जा रहे हैं। बहुत लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर फर्जी वोटरों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के नाम काटे जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है?

आखिर देश या किसी राज्य की सरकार चुनने के लिए वोटर तो उस राज्य या देश का ही होना चाहिए! जो देश के नागरिक ही नहीं हों, उन्हें वोट देने का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने कह दिया कि अगर बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जाते हैं, तो हम हस्तक्षेप करेंगे। बात यह भी समझ में नहीं आई। वोट अगर कटे और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया भी तो फिर होगा क्या? क्योंकि इतना समय ही नहीं बचेगा कि पूरी प्रक्रिया दोहराई जा सके या इतने ज्यादा या इतनी बड़ी मात्रा में करेक्शंस किए जा सकें।

राजनीतिक विपक्ष मजबूत भी हो और जिम्मेदार भी...

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर उसमें उतनी ही परिपक्वता भी हो कि वह देशहित के मामलों में सरकार का सकारात्मक सहयोग कर सके और दिशा भटकने पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके। बहरहाल, सवाल-दर-सवाल जारी हैं और समाधान की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि चुनाव आयोग अपनी शुद्धता या निष्पक्षता कैसे साबित करता है और इन सवालों के जाल से किस परिपक्वता के साथ बाहर निकल पाता है।

हालात पक्ष में ना रहें, तो भी आत्मविश्वास रखें

शुभमन गिल

भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड में अपने टॉप फॉर्म के कारण चर्चा में हैं। उनका मानना है कि बहुत से लोग मानसिक दृढ़ता को नहीं समझ पाते हैं। यह बहुत आसान होता है कि आप खुद को यह कहकर गिरा लें कि मैं पिछले तीन मैचों में अच्छा नहीं खेला या मैं ऐसे आउट हुआ... वगैरह-वगैरह। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या आप खराब प्रदर्शन के बाद भी स्थिर रह सकते हैं? क्या आप उसी सोच, उसी जोश के साथ अगली पारी में उतर सकते हैं? अगर हां, तो आपके पास हमेशा ज्यादा अच्छे दिन होंगे और आप खुद से ज्यादा संतुष्ट भी रहेंगे। आपके मन में पछतावा बहुत कम होगा।

वे कहते हैं, मैं जब टीम से बाहर रहकर रिहैब टाइम काट रहा था तो काफी निराश था। मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। बैठा-बैठा यही सोचता रहता था कि आखिर मैं कब बड़ी पारी खेलूंगा। जानता था कि मुझे सिर्फ एक अच्छी शुरुआत चाहिए। एक बार शुरुआत मिल जाए, तो मैं जानता हूं कि मैं 'ऑन' हो जाता हूं। उस समय मेरा सबसे बड़ा सपना था कि पहला इंटरनेशनल शतक लगा दूं। लेकिन शायद मैं उस लक्ष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा कोशिश करने में लगा था। शतक की सोच मुझ पर इतना हावी हो गई थी कि वो बोझ बन गई। मैं खुद से कहता था- 'तुम पहले काफी पारियां खेल चुके हो, ऑस्ट्रेलिया में एक मौका गंवाया है, अब दोबारा नहीं गंवाना है।' तभी मुझे अहसास हुआ कि मैं खुद पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा हूं। फिर चोट लग गई, तो उसके बाद प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद आईपीएल आया। मुझे एक नई टीम मिली, टूर्नामेंट में टीम जीती और मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद मुझे वनडे टीम में और मौके मिले। मैंने 6 अच्छे वनडे खेले और तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे मेरी लय मिल गई है। जब मैंने जिम्बाब्वे में पहला शतक लगाया, तभी मुझे अंदर से लगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं।

ऐसा खेलने की क्षमता तो हमेशा से मेरे अंदर थी। मैं मानता हूं कि मेरा 100 प्रतिशत खेल और व्यक्तित्व अभी लोगों ने देखा ही नहीं है। 100 प्रतिशत से मेरा मतलब सिर्फ रन बनाने से नहीं है, बल्कि उस खेल से है जिसे मैं अंदर से महसूस करता हूं। मैं जब बड़ी पारी खेलता हूं, उसके बाद जो अगली पारी होती है, वो ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार फॉर्म मिल जाए, तो फिर मैं अपने असली खेल में लौट आता हूं। यह बहुत निजी अनुभव है। अगर मेरी तीन-चार पारियां खराब हो जाती हैं, तो मैं तुरंत नेट्स पर जाकर अपनी तकनीक नहीं बदलता। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने खेल पर भरोसा नहीं करते। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है, भले चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही हों। अगर आपने तीन मैचों में रन नहीं बनाए, तो खुद से कहें कि अगले तीन में बड़ा स्कोर आएगा। अगर आप हर मैच में उसी मानसिकता से उतरते हैं, जैसी पहले में थी, तो सफल होंगे। अगर आप हर बार नजरिया बदलते रहते हैं क्योंकि पिछला मैच खराब था, तो बुरे मैच अच्छे मैचों से अधिक होंगे। आपको उसी सोच पर अडिग रहना होगा, जो सीरीज के पहले मैच में बनाई थी। ये मुश्किल होता है, लेकिन करना ही होगा।

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-सिनेमा अउ रंगमंच के जानेमाने कलाकार रघुवीर यादव के कहना हे जी भैरा के छत्तीसगढ़ ल जानना हे, त पहिली हकन के चार महीना इहाँ के चारोंमुड़ा के गाँव गँवई म किंजर-किंजर के इहाँ माटी, बोली अउ आत्मा ल महसूस करव, तेकर पाछू कुछू लिखिहौ या रचिहौ तभे वोमा असल भाव आही.

-बने तो कहे हे जी कोंदा.

-रायपुर म 90 दिवसीय राष्ट्रीय रंगमंच कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह म अतिथि के रूप म उन गोठियावत रिहिन हें.. वो मन कहिन- आज हम अपन जड़ ले कटत जावत हन इही ह सबले बड़े चिंता के बात आय.. आने-आने जगा के फिलिम मनला देख के उँकर नकल करई ल छोड़व.. नहीं ते उँहचे अटके रहि जाहू.

-एकदम पोठ गोठ कहे हे संगी.. अभी छत्तीसगढ़ी के नॉव म इहाँ के जतका फिलिम मनला देख उँकर कहना ह साक्षात जनाही.. हमर इहाँ नकलचोट्टई के छोड़ अउ कुछू नइ जनावय.. छत्तीसगढ़ अउ छत्तीसगढ़ी के आत्मा ल देखे बर तरसे असन जनाथे.

-सही आय संगी.. गीत-संगीत के क्षेत्र होय या फिलिम के सबो म भेंड़ियाधसान ही जनाथे.. कभू कभार भुले-भटके म एकाद ठ ह बस अपन कस जनाथे.

अहंकार को इतना बड़ा मत करो कि वो क्रोध में बदले

कोई कितने ही संकल्प ले ले, क्रोध छूटता नहीं है। क्रोध करने के बाद लगता है ठीक नहीं किया, पर क्रोध आता है। तो एक काम करिए- क्रोध की सीमारेखा तय करिए घर में, और घर के बाहर। घर में जाहिर है अपने ही लोगों पर गुस्सा आता होगा। बाहर की दुनिया में यदि आपके पास नेतृत्व है तो गुस्से का रूप अलग है और यदि मातहत कार्य कर रहे हैं तो गुस्से का रूप अलग। पर आता सबको है। क्रोध से प्रेरणा भी मिल सकती है। क्योंकि क्रोध जिस ऊर्जा से सक्रिय होता है, वही संकल्प-शक्ति में बदल जाती है। क्रोध की ऊर्जा यदि विद्रोह में बदल गई तो उदासी आ जाती है।

अब दिन-ब-दिन क्रोध और बढ़ेगा। जरा-जरा सी बात पर गुस्सा आएगा नई पीढ़ी को, जिसके लक्षण दिख भी रहे हैं। तो क्रोध गिराना हो तो अपने अहंकार पर काम करिए। अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, बीच का ये जो खेल है, इसमें अहंकार को इतना बड़ा मत करिए कि वो थोड़ी-थोड़ी देर में क्रोध में बदले। क्रोध का परिणाम स्वास्थ्य, संबंध और संतान- तीनों पर बुरा ही पड़ता है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

मालेगांव ब्लास्ट केस में पीएम मोदी और सीएम योगी को फंसाने की थी साजिश?

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जांच कर रहे अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अन्य का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश की थी.

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा को दी राहत

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई 2025) को प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उन्हें (आरोपियों को) दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल सात लोगों पर ही मुकदमा चला, क्योंकि आरोप तय होने के समय बाकी सात को बरी कर दिया गया था.

अधिकारियों ने झूठ बोलने के लिए प्रताड़ित किया

प्रज्ञा ठाकुर ने शनिवार (2 अगस्त 2025) को कहा, "उन्होंने मुझसे कई लोगों के नाम लेने को कहा, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव भी शामिल हैं. यह सब करने के लिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया. मेरे फेफड़े जवाब दे गए, मुझे अस्पताल में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया. मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मुझसे पीएम मोदी का नाम लेने को भी कहा. मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि वे मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे थे." प्रज्ञा ठाकुर का दावा उस मामले में आए फैसले के तुरंत बाद आया है जिसमें बयान से पलटने वाले एक गवाह ने भी दावा किया था कि उसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े चार अन्य लोगों को फंसाने के लिए मजबूर किया गया था. इसमें आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार भी नाम शामिल था.

एटीएस के पूर्व सदस्य ने भी लगाया आरोप

एटीएस के पूर्व सदस्य महबूब मुजावर ने भी दावा किया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया था. हालांकि मुजावर ने शुक्रवार को भी दावा किया कि इस आदेश का उद्देश्य जांच को गलत दिशा में ले जाना और इसे भगवा आतंकवाद का मामला बनाना था.

मालेगांव विस्फोट मामला

देश में सबसे लंबे समय तक चले आतंकवादी मामलों में से एक 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सात लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने, आईपीसी के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमे चलाये गये. मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 घायल हुए थे.

आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता हैः प्रज्ञा

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होकर पहली बार भोपाल पहुंचीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का धर्म भी होता है और रंग भी होता है. उन्होंने कहा, 'हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं, मुस्लिम आतंकवाद होता है, उसी को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द बनाया गया. ये कांग्रेस का षड्यंत्र था. पहलगाम में में जिस तरह से कपडे उतार-उतार कर जांच करके मारा. उन्होंने हिंदुओं को चुन चुनकर मारा है.' मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को साध्वी प्रज्ञा ने दिग्भ्रमित बताया है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम भी लेना खराब है. वो दिग्भ्रमित हैं, उनका नाम ले लो तो दिन खराब हो जाता है. साध्वी प्रज्ञा ने फिर दोहराया कि उन्हें आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पीएम मोदी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरों का नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया था. उन्होंने कहा, 'मुझसे बहुत बड़े-बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा गया, जो मैंने नहीं लिए. उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया।

गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी

नागपुर। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी वाली कॉल झूठी थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि झूठी धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है कि क्या आरोपी का पहले भी ऐसी ही कोई शरारत का रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर में बम लगाने की झूठी धमकी देने वाले एक शख्स को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नागपुर के डीसीपी रुशिकेश सिंगारेड्डी ने बताया कि उन्हें एक फोन आया जिसमें कहा गया कि नितिन गडकरी के घर में बम लगाया गया है और वह जल्द ही फटने वाला है। इस फोन के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बम स्क्वॉड को बुलाया गया, केंद्रीय मंत्री के घर की सुरक्षा को सतर्क किया गया और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बम स्क्वॉड ने घर की पूरी तरह से जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब पुलिस को समझ में आ गया कि यह एक झूठी कॉल है। इसके बाद पुलिस ने फोन करने का लोकेशन ट्रेस किया और उसे ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि इस मामले में उमेश राउत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कॉल उसी के फोन से किया गया था।

प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा

बेंगलुरू। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार (2 अगस्त 2025) को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान प्रज्वल घबराया हुआ दिखाई दिया और जब जज ने उसे दोषी करार दिया तो वह रो पड़ा. उसने कोर्ट से कम सजा की गुहार भी लगाई थी. मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था.

यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है. साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था. इस मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

ऑनलाइन बेटिंग ऐप बंद करने, सुप्रीम कोर्ट का फरमान

नई दिल्ली। ऑनलाइन सट्टेबाजी (betting) बंद करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. मामले में केंद्र से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई की बात कही है. सुनवाई में कोर्ट ने राज्यों के अलावा RBI, TRAI, ED और कुछ गेमिंग कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है. ईसाई धर्म प्रचारक के.ए. पॉल की याचिका में ऑनलाइन बेटिंग को जुआ घोषित कर बंद करवाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि बड़े-बड़े अभिनेता और खिलाड़ी बेटिंग ऐप का प्रचार करते हैं. लाखों लोग अपने पैसे इनमें गंवा रहे हैं. अकेले तेलंगाना में हजारों लोगों ने इसके चलते आत्महत्या की है. 25 से ज्यादा बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेता ऑनलाइन बेटिंग ऐप का प्रचार कर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाला खिलाड़ी भी इसका प्रचार कर रहा है।

तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उन्होंने दावा किया था है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है. तेजस्वी के अनुसार उन्होंने जो EPIC नंबर (RAB2916120) शेयर किया, वो रिकॉर्डस में नहीं है. चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए EPIC नंबर RAB2916120 का विवरण मांगा है ताकि इसकी जांच की जा सके. तेजस्वी यादव को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा, "आपकी ओर से 2 अगस्त 2024 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं होने की बात बताई गई. जांच में पाया गया कि आपका नाम मतदान केन्द्र संख्या 204 (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन) के क्रम संख्या 416 पर अंकित है, जिसका EPIC नंबर RAB0456228 है."

चुनाव आयोग ने कहा, "प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने (तेजस्वी यादव) बताया कि आपका EPIC नंबर RAB2916120 है. जांच में पाया गया कि ऐसा कोई EPIC नंबर चुनाव आयोग की ओर से जारी ही नहीं किया गया है." चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से EPIC नंबर RAB2916120 का पूरा विवरण (वोटर आईडी कार्ड सहित) देने को कहा है, ताकि इस मामले की जांच की जा सके. चुनाव आयोग ने शनिवार को तेजस्वी यादव के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के संबंधित हिस्से में उनका नाम क्रम संख्या 416 पर है.।

राज्यसभा में एक बार फिर BJP का आंकड़ा 100 के पार

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अप्रैल 2022 के बाद पहली बार राज्यसभा में पार्टी ने 100 सांसदों का आंकड़ा पार किया है. तीन मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल हुए हैं. चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है. पिछले महीने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर इस सप्ताह बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी के सदस्यों की संख्या 102 हो गई है. राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों सहित 240 सांसद हैं और 5 सीटें अभी भी खाली हैं. साल 2022 में 13 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनावों के बाद बीजेपी भारत के इतिहास में संसद के ऊपरी सदन में 100 से ज़्यादा सांसदों वाली दूसरी पार्टी बन गई थी।

रूस में भयंकर भूकंप के बाद ज्वालामुखी फटा

मास्को। रूस के कामचटका में बीते दिनों 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके कुछ दिनों बाद ही 450 साल से शांत एक ज्वालामुखी फट गया है। क्राशेनिनिकोव नाम के इस ज्वालामुखी के फटने से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार उठा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। आपातकालीन सेवाओं ने इस ज्वालामुखी के फटने के बाद विमानों के लिए 'ऑरेंज' एविएशन अलर्ट जारी किया है।

स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के ग्लोबल वोल्केनिज्म प्रोग्राम के मुताबिक, क्राशेनिनिकोव ज्वालामुखी 1550 के बाद से शांत था। रूसी राज्य मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में राख का विशाल गुबार साफ देखा जा सकता है। कामचटका के आपातकालीन मंत्रालय ने टेलीग्राम पर बताया कि राख का गुबार ज्वालामुखी से पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर की ओर फैल रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके रास्ते में कोई भी आबादी वाला इलाका नहीं है और अभी तक किसी भी जगह राख गिरने की खबर नहीं आई है।

शक्तिशाली भूकंप और फिर जारी हुई थी सुनामी की चेतावनी

यह ज्वालामुखी विस्फोट उस शक्तिशाली भूकंप के ठीक बाद हुआ है, जिसने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी। इस भूकंप की वजह से जापान से लेकर हवाई और इक्वाडोर तक के तटीय इलाकों में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। अधिकारियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा नुकसान रूस में हुआ, जहां सुनामी ने सेवेरो-कुरिल्स्क के बंदरगाह में एक मछली पकड़ने के कारखाने को भी नुकसान पहुंचाया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, यह 8.8 तीव्रता का भूकंप रूस के कामचटका प्रायद्वीप में पेट्रोपावलोव्स्क के पास आया था और यह 2011 में जापान में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप था।

भारत-इंग्लैंड ने मिलकर की 70 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

शुभमन गिल एंड टीम ने रचा इतिहास

नई दिल्ली। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2025 में कुल 21 शतक लगे हैं. ये सीरीज शतकों के नाम रही है. शुभमन गिल सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने कुल 4 शतक जड़े. हालांकि फिर भी 70 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा नहीं, हालांकि भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मिलकर इसकी बराबरी जरूर कर ली.

शतकों के मामले में भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड से आगे रहे. टीम इंडिया की तरफ से सीरीज में 12 शतक आए, जबकि 9 शतक इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जड़े. द ओवल में खेले जा रहे 5वें टेस्ट में भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा. इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जो रुट और हैरी ब्रूक ने सेंचुरी जड़ी. पाँचों टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक पहले मैच में आए थे, जहां भारत की दोनों पारियों में 5 और इंग्लैंड की पारी में 2 शतक आए थे. 1955 में ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में 21 शतक लगे थे, तब से एक सीरीज में इतने शतक कभी नहीं लगे थे. लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2025 में ऐसा हुआ. ब्रूक ने सीरीज की 20वीं और जो रुट ने 21वीं सेंचुरी जड़ी. हालांकि 1955 में बना 70 साल पुराना रिकॉर्ड टूट नहीं पाया.

इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने 12 शतक लगाए हैं, जबकि वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऐसा सिर्फ चौथी ही बार हुआ. कप्तान शुभमन गिल ने 4 शतक लगाए हैं, उन्होंने 269 रनों की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी. एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बराबरी कर ली.

पहले टेस्ट में लगे शतक
यशस्वी जायसवाल (101)
शुभमन गिल (147)
ऋषभ पंत (134)
ओली पोप (106)
केएल राहुल (137)
ऋषभ पंत (118)
बेन डकेट (149)

दूसरे टेस्ट में लगे शतक
शुभमन गिल (269)
हैरी ब्रूक (158)
जेमी स्मिथ (184)
शुभमन गिल (161)

तीसरे टेस्ट में लगे शतक
जो रुट (104)
केएल राहुल (100)

चौथे टेस्ट में लगे शतक
जो रुट (150)
बेन स्टोक्स (141)
शुभमन गिल (103)
वाशिंगटन सुंदर (101)
रवींद्र जडेजा (107)

पांचवें टेस्ट में लगे शतक
यशस्वी जायसवाल (118)
जो रुट (105)
हैरी ब्रूक (111)

साउथ अफ्रीका ने जीता लीजेंड्स चैंपियनशिप

नई दिल्ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ लीजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए. ये बड़ा लक्ष्य भी एबी डिविलियर्स की तूफानी पारी के आगे बौना सा लगा, साउथ अफ्रीका ने 16.5 ओवरों में इसे हासिल कर 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. डिविलियर्स को फाइनल और डब्ल्यूसीएल 2025 टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया. मोहम्मद हफीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. सलामी बल्लेबाज शरजील खान ने 44 गेंदों में 76 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, इसमें उन्होंने 4 छक्के और 9 चौके लगाए थे. उम्र अमीन ने अंत में 19 गेंदों में 3 छक्के और इतने ही चौके लगाकर नाबाद 36 रन बनाए. आसिफ अली ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए. पाकिस्तान चैंपियंस ने 20 ओवरों में 195 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स ने पहले विकेट के लिए 6 ओवरों में 72 रन बनाए. आमला 14 गेंदों में 18 रन बनाकर साइड अजमल की गेंद पर कैच आउट हुए. डिविलियर्स ने विस्फोटक अंदाज में पारी का आगाज किया और इसे पहले विकेट गिर जाने के बाद भी जारी रखा. डिविलियर्स ने शतकीय पारी खेली. उन्होंने 60 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 120 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 12 चौके जड़े.

सोहैल तनवीर ने 2 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने 16 की इकॉनमी से 32 रन दिए. इमाद वसीम ने 2 ओवरों में 38 रन खर्चे. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए वहाब रियाज ने 3 ओवरों में 33 रन दिए. कुल मिलाकर डिविलियर्स ने पाकिस्तान के हर मुख्य गेंदबाज की पिटाई की. जीन पॉल डुमनी ने भी 28 गेंदों में 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, इसमें उन्होंने 2 छक्के और 4 चौके जड़े. साउथ अफ्रीका ने 19 गेंद शेष रहते 9 विकेट से मुकाबले को जीत लिया. डिविलियर्स की पत्नी इसके बाद ग्राउंड पर आईं, वह बहुत खुश थे.

रूस-अमेरिका के बीच टेंशन, बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत

नई दिल्ली। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से तेल के ग्लोबल सप्लाई में रूकावट आ सकती है. ऐसे में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए ऑयल मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि इससे आने वाले महीनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है. भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने से तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. वेंचुरा में कमोडिटीज और CRM हेड एनएस रामास्वामी ने कहा, "ब्रेंट ऑयल (अक्टूबर 2025) की कीमत 72.07 डॉलर से शुरू होकर 76 डॉलर तक पहुंच सकती है. 2025 के अंत तक कीमत के 80-82 डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए 10-12 दिनों की समय सीमा दी है. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध और 100 परसेंट सेकेंडरी टैरिफ लगने का जोखिम है. इससे तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर भारत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है और इसलिए अपने आर्थिक हितों को लेकर सतर्क रहने की भी जरूरत है. हाल ही में मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसकी योजना 2035 तक अपनी जीडीपी को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 10.6 ट्रिलियन डॉलर करने की है. आज वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा. हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे युवाओं के लिए रोजगार इनके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं. सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है." देश में महंगाई कंट्रोल में है, निर्यात रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, ग्रामीण स्तर पर भी विकास हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है.

वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन सालाना आधार पर 7.5 परसेंट बढ़कर 1,95,735 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसके साथ ही लगातार सातवें महीने कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा. अप्रैल-जुलाई 2025 में कलेक्शन सालाना आधार पर 10.7 फीसदी बढ़कर 8,18,009 करोड़ रुपये हो गया है।

मैंने धनश्री को कभी धोखा नहीं दियाः चहल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री की शादी साल 2020 में हुई थी. शादी के बाद इन दोनों का रिश्ता केवल पांच सालों तक चला और 2025 में चहल-धनश्री ने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया. धनश्री से तलाक के बाद चहल ने पहली बार इस रिश्ते पर बयान दिया है.

राज शमानी के पॉडकास्ट में युजवेंद्र चहल ने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया. राज शमानी ने जब भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से पूछा कि आपको सबसे बड़ा झूठ कौन सा लगा, तब चहल ने कहा कि 'जब मेरे तलाक के वक्त बात हो रही थी और मुझे चीटर (धोखेबाज) कहा जा रहा था, वो सब मुझे बहुत बुरा लगा'. चहल ने आगे कहा कि 'मैं एक ऐसा इंसान हूं, जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मेरे जैसा रॉयल इंसान तो कहीं मिलेगा भी नहीं'. युजवेंद्र चहल ने आगे बताया कि 'अपनों के लिए मैं हमेशा दिल से सोचता हूं. मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, मैंने हमेशा दिया है. मेरे घर में भी मेरी दो बहन हैं, मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे अच्छी चीजें सिखाई हैं, मेरे आस-पास के लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है'.

TCS को एक झटके में 47000 करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते आई गिरावट के चलते देश की कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा. आलम यह रहा कि दस सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से सात कंपनियों के टोटल मार्केट कैप में 1.35 लाख करोड़ की गिरावट आई. इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) सबसे ऊपर है. बीते हफ्ते बीएसई बेंचमार्क इंडेक्स में 863.18 अंक या 1.05 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंफोसिस, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप कुल मिलाकर 1,35,349.93 करोड़ कम हुआ है. इसके विपरीत, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप में उछाल आया. दोनों कंपनियों को सामूहिक रूप से 39,989.72 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ।

भारत से टैरिफ दुश्मनी और पाक से ऑयल डील

आखिर रूसी तेल से क्यों तिलमिलाए हैं ट्रंप?

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं लेकिन मित्र कह-कहकर धोखा देना उनकी पुरानी आदत है, ऐसा उन्होंने अपने करीबी मित्र एलन मस्क के साथ भी किया है और अब भारत के साथ कर रहे हैं.

साल 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया था. तब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, 'पश्चिमी प्रतिबंध कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक अवसर है. आइए हम आत्मनिर्भर बनें. भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा'. आज 27 साल बाद हम फिर से उसी स्थिति में हैं. जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनॉमी है तो अमेरिका ने हम पर 25% टैरिफ लगा दिया है. यानी फिर से हमारे लिए एक चुनौती है और इसे अवसर में बदलने का मौका भी.पिछले 24 घंटे से दुनिया भर में ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की चर्चा हो रही है. इसके केंद्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं. पिछले 24 घंटे में ट्रंप पांच बार बयान दे चुके हैं और पांचों बयान अलग-अलग तरह के हैं. इन बयानों में उनका सबसे ज्यादा हताशा वाला बयान ये है कि भारत की इकोनॉमी डेड है. उनके बयान से लगता है कि भारत उनके रहमों करम पर है, जबकि सच ये है कि 140 करोड़ लोगों का देश ना पहले कभी अमेरिका के रहमों करम पर था, ना अब है और ना आगे कभी रहेगा.ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जो कहा है, उसमें तथ्यों की मात्रा कम और हताशा की मात्रा बहुत ज्यादा है, ट्रंप थोड़े बहके-बहके लग रहे हैं. इसलिए जरूरी है कि उनके स्वार्थी और तंग विचारों की तर्कों और तथ्यों के साथ मरम्मत की जाएगी. दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हैं, वो कब क्या करेंगे और कब क्या बोलेंगे उन्हें पता नहीं होता है. या फिर ये हो सकता है कि बड़बोले बयानों के जरिए दबाव बनाने वाली रणनीति पर काम करते हैं.

मित्र कह-कहकर धोखा देना पुरानी आदत

वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं लेकिन मित्र कह-कहकर धोखा देना उनकी पुरानी आदत है, ऐसा उन्होंने अपने करीबी मित्र एलन मस्क के साथ भी किया है और अब भारत के साथ कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, भारत, अमेरिका का दोस्त है लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं. भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं।

साप्ताहिक शहर सत्ता

कुम्हारी टोल प्लाजा पर 'अवैध वसूली'

बीजेपी सांसद बोले बंद करो, कांग्रेस ने उठाए सवाल- संरक्षण किसका है?

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सफर कर रही आम जनता से कुम्हारी टोल नाके पर कथित अवैध वसूली को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। रायपुर-भिलाई नेशनल हाईवे पर स्थित इस टोल प्लाजा को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने इसे एक "टोल टैक्स घोटाले" की संज्ञा दी है और पूछा है कि जब खुद भाजपा के वरिष्ठ सांसद ने इसे अवैध बताया है, तो वसूली किसके संरक्षण में जारी है?

क्या है मामला?

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुम्हारी टोल प्लाजा से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, और इनसे अवैध रूप से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब खुद भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस टोल नाके को अवैध घोषित कर चुके हैं, तो फिर इसे अब तक बंद क्यों नहीं किया गया?

बीजेपी सांसद का विरोध, फिर भी वसूली

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर टोल प्लाजा को बंद कराने की लिखित मांग की थी। उन्होंने इस संबंध में विवरण सहित दस्तावेज भी सौंपे थे।

इसके बावजूद आज तक वहां से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे आम जनता को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।

ये पैसा आखिर जा कहां रहा है?

धनंजय ठाकुर ने यह भी पूछा कि वसूले जा रहे टोल टैक्स की रसीदें किसके नाम की दी जा रही हैं, और यह रकम किस खाते में जमा हो रही है? कांग्रेस ने इसे एक गंभीर आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

कांग्रेस का आंदोलन और जनता की पीड़ा

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी शिकायत पत्र सौंपा है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। धनंजय ठाकुर ने कहा, 'सवाल यह है कि जब भाजपा के ही सांसद इस टोल को अवैध बता रहे हैं, तो वसूली किसके इशारे पर हो रही है? कौन है जो टोल संचालकों को संरक्षण दे रहा है?'

विपक्ष से उठे सवाल, सत्ता में चुप्पी क्यों?

इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण या कार्रवाई नहीं आई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब स्वयं भाजपा के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, तब इस अवैधता को रोकने में सरकार की निष्क्रियता संदेह पैदा करती है।

टोल टैक्स या टोल घोटाला?

कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर उठ रहे ये सवाल केवल वसूली की वैधता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह मुद्दा अब जनहित, पारदर्शिता और शासन की जवाबदेही से भी जुड़ गया है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से इस टोल की वैधता पर उंगलियां उठ रही हैं, तब जनता जानना चाहती है कि आखिर यह वसूली बंद क्यों नहीं हो रही है?

अग्रिम जमानत के लिए भूपेश बघेल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

रायपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप जैसे मामलों में नाम सामने आने के बाद पूर्व सीएम बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है. याचिका में पूर्व सीएम बघेल ने मांग की है कि उन्हें इन मामलों में गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है.भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के तहत की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है. आशंका जताई है कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कर सकती है.

चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई

पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की दाखिल जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है. चैतन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि न तो उनका नाम ED की एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में, इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं. उनका नाम ईडी की एफआईआर में नहीं है.

सरकार की लापरवाही से सड़कों पर दम तोड़ रहा गौधन : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश भर मे गायों के सड़को पर कुचल कर मारे जाने की घटना को सरकार की लापरवाही और उपेक्षा का परिणाम बताते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा गाय के नाम पर केवल राजनीति करती है, असलियत यह है कि विगत डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में गौवंशी पशुओं की संख्या तेजी से घट रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इस सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दुर्भावना पूर्वक गौठानो में ताले लगा दिए, गौ अभ्यारण के दावे केवल कागजी हैं। रोज दर्जनों गाएं सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होकर बेमौत मारी जा रही हैं, किसान खुली चराई से परेशान हैं और राहगीर भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। विगत दिनों बिलासपुर मे 25 गाय कुचल कर मारी गयी विगत 25 दिन के भीतर एक साथ बड़ी संख्या में हाईवे पर गायों के कुचल कर मारे जाने की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 13 जुलाई को रतनपुर-पेंड्रा मार्ग पर इसी तरह से 14 गायें सड़क पर एक साथ कुचलकर मार दी गई थी, राजधानी के निकट किरना में ऐसे ही 18 गौवंशी पशुओं को ठोकर मारकर मौत के घाट उतारा गया था। विगत दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मवेशियों को सड़क से हटाने का दिशा निर्देश दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सरकार कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई, इसी की वजह से हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार के प्रयास केवल कागजी हैं।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि गौठान बंद करने का दुष्परिणाम अब सड़को पर दिख रहा है। भाजपा की सरकार की गौ संरक्षण को लेकर ना कोई नीति है ना ही नियत। नई व्यवस्था तो छोड़िए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित 10 हजार से अधिक गौठान जिसमें से लगभग 8 हजार गौठान आत्मनिर्भर हो चुके थे,।

कांग्रेस ने 60 साल तक पिछड़ा वर्ग के साथ किया धोखाः साव

बिलासपुर। आज पिछड़ा समाज राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। और विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को आत्मसात करके देश की ताकत बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी पिछड़ा वर्ग समाज के हित के बारे में नहीं सोचा और ना ही कोई कार्य किया। जबकि मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। जिसका लाभ समाज उठा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ये बातें सिम्स ऑडिटोरियम, बिलासपुर में आयोजित भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संभागीय सम्मेलन में कही। श्री साव ने कहा कि, जब कांग्रेस की जमीन खिसक गई तो पिछड़ा समाज के बारे में याद आ रही है और उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, जिस कांग्रेस ने 60 साल तक अन्य पिछड़ा वर्ग की सुध नहीं ली, आज अचानक डोरे डाल रही है। राहुल गांधी अन्य पिछड़ा वर्ग से माफी मांग रहे हैं। आज पिछड़ा समाज जानता है, कौन उनका हितैषी है और किसने उनका वर्षों तक उपयोग किया, पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी के शासन वाले भारत में हर वर्ग प्रगतिरत है। अब कांग्रेस कभी अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होगी। श्री साव ने संभागीय सम्मेलन में मोदी सरकार के 11 साल के विकास कार्यों को लेकर जन जागरूकता करने कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया

ननों की जमानत सत्य की जीत : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एनआईए कोर्ट से ननों की जमानत से सच्चाई की जीत हुई। भाजपा ने अपने पोलिटिकल प्रोपोगंडा के लिए बेकसूर ननों को गिरफ्तार किया था। ननों पर तीन महिलाओं के धर्मांतरण का आरोप एवं मानव तस्करी का आरोप लगाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि ये ननें जिन तीन महिलाओं को लेकर जा रही थी वे सभी बालिग है तथा अपने परिजनों की सहमति से नौकरी के लिए जा रही थी। जिन तीन महिलाओं को ननों के साथ पकड़ा गया था उनमें से एक ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि बजरंग दल के लोगों ने मारा-पीटा और धमकाया। हम लोग स्वेच्छा से नौकरी के लिए जा रहे थे। महिला ने यह भी बताया कि बजरंग दल के लोगों ने इन आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट भी किया था। एक तरफ भाजपा सरकार महिलाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, महिलाएं रोजी-रोटी की तलाश में पलायन कर रही है। दूसरी तरफ स्वेच्छा से नौकरी के लिए बाहर जाने वाली महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा, उनकी मदद करने वालों पर झूठे आरोप लगाकर राजनीति की जा रही थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कवर्धा जिले के बोड़ला थाने के अंतर्गत पुलिस की प्रताड़ना और भाजपा सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण एक युवक माखन लाल यादव ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने चोरी के माल खरीदने के संदेह में उसके छोटे भाई गोपाल यादव को जेल में बंद कर रखा है। बताया जाता है कि कुछ लोग युवक गोपाल के पास चांदी का गहना लेकर पहुंचे जिसे गोपाल ने वाट्सअप पर पोस्ट किया कि यह किसका है। इसी पोस्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों भाईयों को थाने बुला कर बैठा लिया तथा ढाई लाख रुपयों की मांग किया। पैसे नहीं देने पर दोनों को फंसाने की धमकी दिया। बड़े भाई को पैसे की व्यवस्था के लिए छोड़ दिया, उससे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो विचलित होकर उसने आत्महत्या कर लिया, जिसका विरोध बोड़ला के लोगों ने चक्का जाम भी किया, जैसे ही बड़े भाई ने आत्महत्या किया तो छोटे भाई के खिलाफ पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लिया। गृह मंत्री के गृह जिले में आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डेढ़ माह हो चुके हैं स्कूल खुले लेकिन अब तक यह सरकार बच्चों को किताब वितरित नहीं कर पाई है। इस सरकार के सरकारी सिस्टम में खामियों की सजा पूरे प्रदेश के बच्चे और शिक्षक भोगने मजबूर हैं।

महाष्टमी की छुट्टी रद्द करने का आदेश वापस ले सरकार

रायपुर। महाष्टमी की सरकारी छुट्टी संशोधित करने के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नवरात्रि में दुर्गा पूजा के आठवें दिन में महाष्टमी की छुट्टी सभी सरकारी दफ्तरों में दी जाती रही है, जिसे भाजपा सरकार के द्वारा रद्द करना बेहद आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। सरकार अपने इस आदेश को तत्काल वापस ले। ये माता भक्तों का अपमान है, आखिर भाजपा को सरकारी कैलेंडरो में महाष्टमी की छुट्टी उल्लेखित करने में आपत्ति क्यों हो रही है? वर्षो से सरकारी कैलेंडर में महाष्टमी की छुट्टी उल्लेखित होते आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार आखिर प्रदेश के परंपरा तीज त्यौहार को बदलने में क्यों तुली हुई? सरकार बनते ही हरेली का त्यौहार नहीं मनाया गया, जब पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की निंदा हुई तब दूसरे बार हरेली तिहार का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन बंद कर दिया गया। माता कौशल्या मंदिर में होने वाले संस्कृति का आयोजन बंद है। कांग्रेस सरकार के दौरान सभी ग्राम पंचायत को सांस्कृतिक और परंपरा के अनुसार सामूहिक रूप से तीज त्यौहार का आयोजन करने सरकारी मद से फंड दिया जाता था।

'प्रोजेक्ट छाँव' के तहत अधिकारी कर्मचारियों का हुआ हेल्थ चेकअप

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रोजेक्ट "छाँव" की शुरुआत की गई है। इसके तहत आज सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में पशुधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, उद्यानिकी, मत्स्य, खाद्य, आबकारी, सहकारिता, नाप तौल, खनिज, जिला मार्केटिंग, आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं परिवारजनों ने स्वास्थ्य जांच करवाया।

प्रोजेक्ट छांव कार्यक्रम में आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा शामिल हुए। उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट छांव सभी शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए एक अच्छी पहल है जिसके माध्यम से उनका मुफ्त इलाज एवं टेस्ट एक छत के नीचे मुमकिन है। पूरा जिला प्रशासन लगातार कार्य करता जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के प्रयास से यह स्वास्थ्य शिविर संभव हो पा रहा है, जिसका लाभ आप सभी शासकीय कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य ले रहे हैं | स्वस्थ्य जीवन जीना ही खुशहाल जीवन है, हमको अपने तथा अपने परिवारजनों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन को मैं इस अद्भुत प्रोजेक्ट के लिए धन्यवाद देता हूं एवं बधाई देता हूं।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. सिंह ने अपने कहा कि प्रोजेक्ट "छाँव" शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 8 विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं उनके परिजनों की स्वास्थ्य जांच की गई।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट छांव के सभी लाभार्थियों को हमारे कॉल सेंटर से फीडबैक कॉल जाता है जिसके माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। एक छत के नीचे सभी प्रकार के इलाज संभव है। अब तक स्मृति पुस्तकालय में 1500 से अधिक किताब और पांच लैपटॉप मिल चुका है। प्रोजेक्ट धड़कन के बाद अब स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए प्रोजेक्ट दृष्टि की शुरुआत होने जा रही है जिसके तहत बच्चों के आंख का मुफ्त इलाज किया जाएगा। अंत्योदय तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है|

स्कूल बैग का बोझ काम करने कलेक्टर रायपुर का सराहनीय प्रयास

शहर सत्ता/रायपुर। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने "बस्ते का बोझ कम करने" की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने धरसीवां विकासखंड के बीईओ अमित तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया है।

इस दल में व्यायाम शिक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने माता सुंदरी पब्लिक स्कूल, खालसा उच्चतर माध्यमिक शाला, पूर्णिमा इंग्लिश मीडियम स्कूल, सालेम इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा सालेम कन्या हिन्दी मीडियम स्कूल का का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राचार्यों और शिक्षकों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों पर शैक्षणिक दबाव कम हो और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा विभाग का यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुविधा और समुचित विकास को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रकार के निरीक्षण अब सतत किए जाएंगे।

1 नवंबर को 'अमृत रजत महोत्सव' में आने सीएम साय ने दिया पीएम को दिया न्यौता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'अंजोर विज़न @2047' दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के "जन विश्वास अधिनियम 2023" से प्रेरणा लेते हुए राज्य में "जन विश्वास विधेयक 2025" पारित किया है।

बिहान योजना बना आर्थिक स्वावलंबन का आधार

- **जैविक खेती और पशुपालन से लखपति दीदी बन रहीं हैं**

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के समन्वित प्रयासों से रायगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। एक समय था जब ग्रामीण महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, किंतु अब वे जैविक कृषि, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से लखपति दीदी के रूप में, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की प्रेरणा बन गई हैं। रायगढ़ जिले की एक लाख 45 हजार 49 महिलाएं अब तक 13 हजार 500 स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। ये समूह न केवल नियमित बचत एवं आंतरिक ऋण प्रणाली का संचालन कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर आजीविका संवर्धन की दिशा में प्रभावी कार्य भी कर रहे हैं। पुसौर, खरसिया और धरमजयगढ़ विकासखंडों में 40-40 कृषि मित्र एवं पशु सखी चिन्हित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कृषि मित्र महिलाओं को जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक दवाओं के निर्माण और उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे 'लखपति दीदी' के रूप में पहचान बना रही हैं।

28 करोड़ से अधिक की बैंक क्रेडिट लिंकिंग

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक जिले के 1,045 समूहों को कुल 28 करोड़ 37 लाख रुपये की राशि बैंक क्रेडिट लिंकिंग के माध्यम से स्वीकृत की गई है। माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में यह राशि प्रदान की जा रही है, जिसका उपयोग महिलाएं कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, लघु उद्योग, मत्स्य पालन सहित विविध आजीविका गतिविधियों में कर रही हैं।

प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में आए 553 करोड़

रायपुर। रायपुर। सावन के पवित्र महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के रूप में 20 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के सभागार से प्रदेश के किसानों के साथ वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस वृहद किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2019 से अब तक देशभर के किसानों को 3.75 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है और पीएम किसान निधि इसका सशक्त उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि विकास में पिछड़े जिलों के लिए 'प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना' की शुरुआत की गई है और इसके लिए 24 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों ने निःशुल्क इलाज का लिया लाभ

आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में टॉप फाइव राज्यों में छत्तीसगढ़

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

राज्य सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई को छत्तीसगढ़ की अपनी दो विशेष योजनाओं — शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना — के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है। इस एकीकृत व्यवस्था से अधिकतम लाभार्थियों को नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार के स्वास्थ्य ढांचे में जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वय वंदन योजना को भी राज्य में मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख से अधिक वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 48% राशन कार्डधारी वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ता, ग्राम सभाएं, शहरी स्वास्थ्य मंच, वृद्धाश्रमों और आवासीय कॉलोनियों में लक्षित पहुंच सुनिश्चित की गई है। साथ ही, 104 कॉल सेंटर के माध्यम से निरंतर संपर्क और सेवा सुविधा दी जा रही है। विशेष प्रयास के तहत 6 जिलों को 'वय मित्र जिला' के रूप में चिह्नित कर राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना रही है।

साप्ताहिक शहरसत्ता

यहां सपनों की कीमत पसीने और संघर्ष से चुकानी पड़ती है

स्टारडम नहीं, बल्कि संघर्ष ही असली पहचान

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

बॉलीवुड हो या छॉलीवुड, हर सफलता के पीछे गुमनाम संघर्ष की कहानियाँ छिपी होती हैं। सिनेमा सिर्फ रोशनी और ग्लैमर का नाम नहीं, बल्कि तपस्या और पसीने से बुना गया वो सपना है, जिसमें हर शख्स की अपनी कहानी होती है।चमक-धमक से भरी सिनेमा की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, उतनी ही कठोर हकीकत उसके परदे के पीछे छिपी होती है।रायपुर, भिलाई से लेकर मुंबई तक, डायरेक्टर, एक्टर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और असिस्टेंट डायरेक्टर का सफर संघर्ष, तपस्या और ज़ब्बे से होकर गुजरता है।यहाँ स्टार बनने से पहले हज़ारों ठोकरें, नाकामियां और निराशाएं झेलनी पड़ती हैं, और वही असली पहचान बनती है।

संजय महानंद: रंगमंच से सिनेमा का सितारा

रायपुर के 46 वर्षीय अभिनेता संजय महानंद ने 1996-97 में गुरुदेव संजय मैथिल की नाट्यशाला से सफर शुरू किया। 'बड़े भाई साहब' जैसे नाटकों से पहचान,फिर 60 से अधिक छत्तीसगढ़ी और 70 भोजपुरी फिल्मों तक का सफर आसान नहीं था।मुंबई में ठहरने के लिए जगह तक न होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।ईश्वर ने मुझे कलाकारी के लिए ही इस धरती पर भेजा है,वे कहते हैं।

प्रियंका सिंह: संघर्षों के बीच उम्मीद की चमक

कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग को पैशन बनाने वाली प्रियंका सिंह बताती हैं कि छॉलीवुड में ड्रेस डिज़ाइनर्स को अभी तक वह पहचान और मेहनताना नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं। फिर भी वे दृढ़ हैं,मैंने कभी अपने क्राफ्ट से समझौता नहीं किया। उनका सपना है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ट्राइबल फैशन को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचाया जाए।

प्रिया साहनी: फैशन और क्रिएटिविटी का संगम

मुंबई से फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई के बाद छॉलीवुड लौटीं प्रिया साहनी का मानना है कि बजट की कमी क्रिएटिविटी को सीमित करती है।कई बार डिज़ाइनर्स को सिर्फ कपड़े अरेंज करने तक सीमित कर दिया जाता है,सही टीम और संसाधन मिलने पर छॉलीवुड का फैशन भी बड़े शहरों की बराबरी कर सकता है।

करुणा देवांगन: पहचान और इज़्ज़त की तलाश

फैशन डिजाइनिंग में ग्रैजुएट करुणा देवांगन पिछले दो साल से शॉर्ट फिल्मों और फीचर फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट काम कर रही हैं। उनका मानना है कि ड्रेस डिज़ाइनिंग को इंडस्ट्री का रूप देने के लिए बजट, प्रोफेशनल टीम और सुरक्षित माहौल ज़रूरी है।महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में सेफ्टी और पहचान सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं.

बॉबी सोनी नागवंशी: कैमरे के पीछे का योद्धा

2019 से बतौर एसोसिएट डायरेक्टर काम कर रहे बॉबी सोनी नागवंशी का कहना है, असली एसोसिएट डायरेक्टर वही है, जो मैनेजमेंट, क्रिएटिव विज़न और प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर हो। सोनी लिव की वेब सीरीज़ जहानाबाद से उन्हें पहली बड़ी पहचान मिली। भविष्य में वे एनिमेशन फिल्मों का निर्देशन करना चाहते हैं।

हिमांशु: हर विभाग को समझने की कला

डायरेक्टर विजन सेट करता है, जबकि एसोसिएट डायरेक्टर उस विजन को ग्राउंड पर एक्सीक्यूट करता है। मानव भावनाओं और रिश्तों पर आधारित फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि दर्शक खुद को उसमें देख सकें और कुछ सीख लेकर जाएं। सिर्फ डायरेक्टर बनने का सपना न देखें, पहले ग्राउंड वर्क सीखें। डायरेक्शन हर विभाग को समझने और मैनेज करने की कला है।

विक्रांत सेनद्रे: नई पीढ़ी का चेहरा

रायपुर के 28 वर्षीय विक्रांत सेनद्रे ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉर्डर और हस झन पगली फँस जाबे जैसी फिल्मों से शुरुआत की। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म जंगल ब्यूटी जल्द रिलीज़ होने वाली है। डायरेक्टर के दिमाग़ में पूरी फिल्म पहले से बनी होती है, और उसे समझना असिस्टेंट का असली इम्तिहान है।

परमजीत सिंह: हर फ्रेम की जिम्मेदारी

भिलाई के परमजीत सिंह ने मनीष मनिकपुरी की फिल्मों गुइयां, रामायण और लमसेना में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर अहम भूमिका निभाई। बरसा टोला गांव में आंधी-तूफान के बीच शूटिंग का अनुभव वे कभी नहीं भूलते। डायरेक्टर तभी सफल होता है जब टीम एक लाइन में चलती है।

ससुराल गेंदा फूल से शुरुआत, ये रिश्ता क्या कहलाता है ने दिलाई पहचान : प्राची

बॉलीवुड फिल्मों की फैशन डिजाइनर प्राची विनायक हट्टीहोली से खास बातचीत

24 घंटे काम, शुरुआती छह महीने बिना वेतन, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यही है प्राची विनायक हट्टीहोली की कहानी, जिन्होंने ससुराल गेंदा फूल जैसे बड़े शो से फैशन डिजाइनिंग का सफर शुरू किया और ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपनी पहचान बनाई। मेहनत, क्रिएटिविटी और नए दौर की सोच के दम पर प्राची आज टीवी इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी हैं।

फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाने वाली प्राची विनायक हट्टीहोली का सफर आसान नहीं रहा। स्टार प्लस के मशहूर शो ससुराल गेंदा फूल से उन्होंने करियर की शुरुआत की, जहां शुरुआती छह महीनों तक उन्हें वेतन तक नहीं मिला, फिर भी उन्होंने 24 घंटे तक काम कर शो की खूबसूरती बनाए रखी।

प्राची कहती हैं कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम सिर्फ कपड़े तैयार करना नहीं होता, बल्कि स्क्रिप्ट, किरदार की सुविधा, निर्देशक और कैमरामैन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हर डिज़ाइन को परफेक्ट बनाना होता है। कभी-कभी बजट के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन यही असली क्रिएटिविटी की पहचान है। उनका करियर टर्निंग प्वाइंट ये रिश्ता क्या कहलाता है रहा, जिसने उन्हें अलग पहचान दिलाई। वह मानती हैं कि कॉस्ट्यूम ट्रेंड्स वक्त के साथ बदलते हैं, इसलिए इन्हें डिजिटलाइजेशन से जोड़ना ज़रूरी है।

छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कभी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वहां के ड्रेस सेंस को देखकर उन्हें यकीन है कि वहां भी पेशेवर डिजाइनरों के लिए सुनहरे मौके हैं। प्राची का संदेश है,अपने टैलेंट को दिखाओ और मेहनत करना कभी मत छोड़ो।

इको टूरिज्म

सिद्धखोल जलप्रपात

जिला मुख्यालय बलौदाबाजार से करीब 40 किमी की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिद्धखोल जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने पहल की गई है। वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने सौंदर्य से भरपूर इस जलप्रपात का निरीक्षण कर परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान को कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है। वनमंडल अधिकारी बताया कि सिद्धखोल जलप्रपात में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाएं विकसित करने वन विभाग एवं वन प्रबंधन समिति कुकरिकोना द्वारा नए नए प्रयास किए जा रहे है।

वन प्रबंधन समिति कुकरिकोना की संचालन में सहभागिता

सिद्धखोल जलप्रपात को संचालन के लिए कुकरीकोना समिति को जोड़ा गया है जिससे कि वहां के बेरोजगार युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके साथ ही वन क्षेत्र की सुरक्षा के साथ-साथ इको पर्यटन के आधार पर जलप्रपात का संचालन हो सके। सके अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा कैंटीन का संचालन एवं टिकट व्यवस्था में सुधार करने की योजना बनाई गई है।

निर्देशनुसार परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान सुनीत साहू द्वारा कुकरीकोना समिति के सदस्यों के साथ मिलकर सिद्धखोल जलप्रपात में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए नई शुरुआत की गई है। जब पर्यटक सिद्धखोल जलप्रपात में प्लास्टिक बोतल लेकर पहुंचेंगे तब जांच नाके पर उनसे निर्धारित शुल्क लेकर एक स्टीकर प्लास्टिक पॉलीथिन में लगाकर दिया जाएगा । वापसी में उक्त स्टीकर लगे प्लास्टिक को वापस जमा करने पर शुल्क वापस कर दी जाएगी।

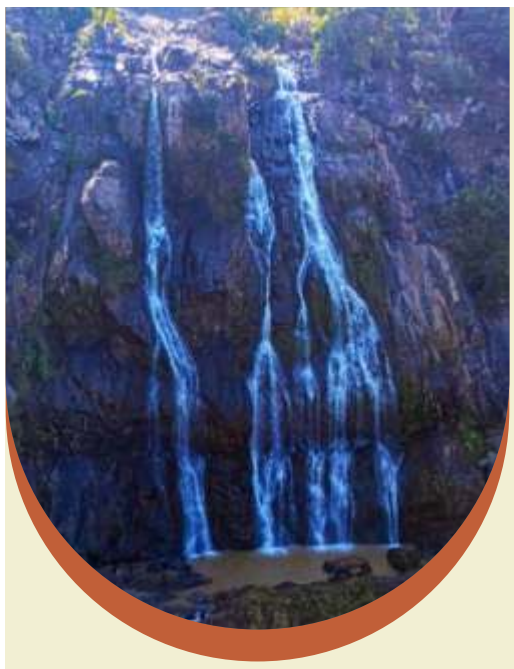

प्राकृतिक छटा, अध्यात्म और संस्कृति से परिपूर्ण जशपुर बना छत्तीसगढ़ का पर्यटन हॉटस्पॉट

छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला जशपुर अब पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरता नाम बनता जा रहा है। जहां एक ओर यहाँ की वादियां, जलप्रपात और पहाड़ियाँ प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिर, गुफाएं और जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम दे रही हैं।

जलप्रपातों की घाटियों में बसी सुंदरता

जिले में स्थित भृंगराज, रानीदाह, दनगरी, छूरी, राजपुरी और मकरभंजा जलप्रपात सैलानियों को अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं। मकरभंजा को छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जबकि 'देश देखा' से 1300 फीट की ऊंचाई से उगते सूरज का दृश्य पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा अनुभव देता है।

साहसिक पर्यटन और नेचर कैंप की भी बहार

मयाली नेचर कैम्प में ईब नदी के तट पर नौकायन और प्राकृतिक दृश्यावलियां रोमांच को नया विस्तार देती हैं। पंडरापाठ की पहाड़ियां, कोतेबिरा के शिलाखंड, फतेहपुर का शांत वातावरण और देश देखा की रॉक क्लाइम्बिंग जैसी गतिविधियां युवाओं को खासा लुभा रही हैं।

अध्यात्म की ओर ले जाते तीर्थ स्थल

जशपुर का उल्लेख बिना मधेश्वर पहाड़, कोतेबिरा शिव मंदिर, कैलाश गुफा, सोगड़ा आश्रम, स्वालिन सरना और किलिकला शिव मंदिर के अधूरा है। मधेश्वर को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा गया है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है।

चाय की खुशबू और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत मेल

सोगड़ा और सालीडीह के चाय बागान इस क्षेत्र को मध्य भारत का एक विशिष्ट चाय पर्यटन केंद्र बनाते हैं। वहीं, सरना एथनिक रिसॉर्ट स्थानीय जनजातीय स्थापत्य और हस्तशिल्प के माध्यम से सांस्कृतिक अनुभव कराता है। जिले में स्थित गुल्लू डैम (बेने डैम) जलविद्युत उत्पादन का भी प्रमुख केंद्र है, जो आधुनिक विकास का प्रतीक है।

आदिवासी संस्कृति को जीवित रखते लोकनृत्य

यहां की पहाड़ी कोरवा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल किया गया है। सरहुल और करमा जैसे पारंपरिक नृत्य इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को सजीव बनाए रखते हैं।

धर्म, आस्था, और व्यवस्था हलाक...

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी

हिन्दू धर्म में गायों का क्या मुकाम है यह बताने की जरुरत नहीं। वैसे भी छत्तीसगढ़ में हिन्दू हितैषी सरकार भी है और 95 फीसदी से अधिक हिन्दू हैं। मानसून में चातुर्मास की वजह से जिन रास्तों से जैन संत-साध्वी पैदल यात्रा करते हैं और श्रावण मास में शिवभक्त जलाहारी लेकर नंगे पैर जिन रास्तों पर चल रहे हैं वो सड़क गौमाता के खून से सराबोर है। ऐसे में सबसे शांत और मृदुभाषी मुख्य सचिव अमिताभ जैन का व्यवस्था को लेकर आगबबूला होना लाजमी है। बुधवार को रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर 18 गायों की दर्दनाक मौत पर अमिताभ ने कलेक्टर, और एसपी के व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिखा, वह हैरान करने वाला था। दो मिनट के भीतर लगातार भेजे चार मैसेज से सूबे के कलेक्टर, एसपी हिल गए। कई कलेक्टर, एसपी ऑफिस और घरों से निकलकर शहरों में गायों को देखने चले गए। एक जिले की पुलिस ने घंटे भर के भीतर दो मवेशी मालिकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें, छत्तीसगढ़ की गोठान बनी सड़कें हाई कोर्ट के संज्ञान में है। हर महीने चीफ सिकरेट्री को होई कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट देनी होती है। बावजूद इसके हफ्ते भर में 90 से अधिक गायों की मौत हो गई, तो सीएस को गुस्सा तो आएगा ही।

शांत और मृदुभाषी मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी आगबबूला

1 महीने में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे में 50 गौधन हलाक

चातुर्मास और श्रावण मास में गौमाता के खून से सनी सडकों पर भक्त

हाई कोर्ट, सीएस के निर्देश के बाद कुछ दिन में सिस्टम पड़ा ढीला

शहर सत्ता/रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर शहरों की मुख्य सड़कों तक, घुमंतू मवेशियों की वजह से होने वाला हादसा अब जानलेवा साबित हो रहा है। बीते एक महीने में अकेले बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है, वहीं रायपुर शहर में हर साल औसतन 15 लोग मवेशियों से जुड़ी दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर जनहित का मुद्दा मानते हुए राज्य सरकार, कलेक्टरों और नगर निगमों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया।

लिमतरा में फिर बड़ा हादसा 15 गायें रौंदी गई

बिलासपुर जिले के लिमतरा के पास 30 जुलाई की रात एक तेज़ रफ्तार अज्ञात वाहन ने हाईवे पर बैठे मवेशियों के झुंड को कुचल दिया। 15 गायों की मौके पर मौत हो गई और कई घायल हो गईं। यह हादसा बीते 20 दिनों में तीसरी बड़ी घटना थी। इससे पहले 14 जुलाई को बारीडीह गांव के पास एक और वाहन ने 22 गायों को रौंद दिया था, जिसमें 17 की मौत हुई थी। इस पूरे महीने में 50 से अधिक गौवंश की मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय गौ सेवकों में आक्रोश है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही और बेतरतीब सिस्टम की वजह से यह हत्याएं हो रही हैं।

रायपुर शहर में भी हालात बेकाबू, हर साल 15 मौतें

राजधानी रायपुर में हर साल औसतन 15 लोगों की मौत मवेशियों की वजह से होती है। बारिश के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि मवेशी सूखी जगह की तलाश में सड़कों पर आ जाते हैं। इस साल भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और कई घायल हुए हैं। वीआईपी रोड, एयरपोर्ट मार्ग, नया बस स्टैंड, कुशालपुर, भनपुरी जैसे इलाकों में हर रोज मवेशी घूमते हैं। ट्रैफिक जाम, वाहन दुर्घटनाएं और झगड़े आम हो गए हैं। गौ रक्षकों ने हाल ही में दो थानों का घेराव किया, जब एक वाहन चालक ने गाय को टक्कर मार दी।

10 साल में न नीति बनी, न फंड आया

पिछले 10 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारें इस मुद्दे पर ठोस नीति नहीं बना पाईं। न पर्याप्त गौठान, न शहरी कांजी हाउस, और न ही स्थायी फंडिंग का कोई प्रावधान। कागज़ों में योजनाएं बनीं, लेकिन अधिकारियों ने फील्ड में काम करना छोड़ दिया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे सुबह-शाम सड़कों पर गश्त करें और मवेशियों को गौठान में पहुंचाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सिस्टम ढीला पड़ गया।

बिलासपुर में धारा 163 लागू, FIR के आदेश

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सड़क पर मवेशी छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। धारा 163 के तहत जुर्माना और मुकदमा दर्ज होगा। इसके बावजूद हाईवे और शहर की सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी जस की तस है।

समस्या वहीं की वहीं, जिम्मेदार कौन?

सवाल उठता है कि आखिर कब तक मवेशी सड़कों पर कुचले जाएंगे? कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? प्रशासनिक सिस्टम हर बार हादसे के बाद कुछ दिन सक्रिय होता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हाईकोर्ट की फटकार और जनदबाव के बावजूद अगर सरकार और प्रशासन नहीं जागता, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि जन जीवन के साथ खेल है।

चरवाहा, पंचायत और स्थानीय नियंत्रण : कोर्ट की दिशा में हलचल

कोर्ट ने चरवाहा नियुक्ति, पंचायत की ज़िम्मेदारी, और स्थानीय निगरानी व्यवस्था को भी लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक उनकी स्थिति भी कागजों से बाहर नहीं आ सकी है।

हाईकोर्ट की फटकार, 'काऊ कैचर क्या सिर्फ दिखावे के लिए हैं?'

बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 1 अगस्त को हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने राज्य शासन, एनएचएआई और पुलिस प्रशासन से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा, 'आपके काऊ कैचर खाली पड़े हैं, क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं? अब इन पर कार्रवाई होगी।' कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल हाईवे पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, रेडियम बेल्ट लगाने का काम अधूरा और शहरी क्षेत्रों में गौठान की कमी के चलते मवेशी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं।

कोर्ट ने मांगा हलफनामा, अगली सुनवाई 19 अगस्त को

हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और एनएच प्रोजेक्ट डायरेक्टर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि मवेशियों को हटाने और गौशालाओं की व्यवस्था के लिए अब तक क्या-क्या किया गया। अगली सुनवाई 19 अगस्त को तय की गई है।

राज्य सरकार की कार्रवाई से कोर्ट असंतुष्ट

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने बताया- 4 गाय मालिकों पर FIR, 9 नई जगह चिन्हांकित, 40 लाख की लागत से शेड निर्माण, सोलर रेडियम अभियान, पहले से SOP लागू, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा—"ये सब प्रतीकात्मक उपाय हैं, ठोस व्यवस्था लाएं।"

NHAI को भी निर्देश

- साइन बोर्ड और बैरियर अनिवार्य
- मवेशी प्रभावित इलाकों में साइन बोर्ड लगाएं
- बम्बू क्रॉस बैरियर जैसे उपाय अपनाएं
- पेंड्रीडीह बायपास की दुकानों की समस्याओं पर संज्ञान लें

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)।